

## मनरेगा भुगतान में वलिंब

### प्रलिमिस के लिये:

**आधार भुगतान बरजि सिस्टम (APBS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम (MGNREGA) योजना**, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (NEFMS),

### मेन्स के लिये:

मनरेगा योजना के तहत वलिंबित भुगतान का मुददा, मनरेगा योजना से संबंधित चुनौतियाँ, आगे की राह और मनरेगा योजना को मजबूत करने के समाधान।

**स्रोत: डाउन टू अरथ**

### चर्चा में क्यों?

2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 (2020-2024) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि केंद्र सरकार पर **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम (MGNREGA) योजना** के श्रमकों को वलिंबित मजदूरी के रूप में 39 करोड़ रुपए बकाया है।

- अध्ययन में वर्ष 2021-22 में 31.36 मिलियन वेतन लेनदेन का वशिलेषण किया गया और पाया गया कि आधार-आधारति भुगतान प्रणाली (ABPS) तथा जाति-आधारति वेतन वितरण ने भुगतान की गतिमें सुधार करने के बजाय देरी का कारण बना है।

### मनरेगा भुगतान से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- ABPS की अकुशलता:** जनवरी, 2024 में ABPS की अनविरायत के बाद केवल 43% मनरेगा श्रमकि ही इसके लिये पात्र थे।
  - ABPS के कारण देशभर में हुई अघोषित देरी की कषतपिरूतिशर्शी 400 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जो भुगतान को सुव्यवस्थिति करने और पारदर्शन में सुधार लाने के सरकार के दावे के विपरीत है।
- अपर्याप्त निधि:** भुगतान में देरी का कारण मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधिका अपर्याप्त होना है।
  - वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 29% भुगतान ही अनविराय 7-दिवसीय अवधि के अंदर संसाधित किये गए।
- बजट आवंटन में कमी:** अध्ययन में मनरेगा के लिये वित्तपोषण की कमी पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 में बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 0.41% (जो ग्रामीण रोज़गार की मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक स्तर से काफी कम है) था।
  - कोविड-महामारी (वर्ष 2020-21) के दौरान यह केवल 0.56% था, जो वित्त वर्ष 2023-24 एवं वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 0.2% रह गया।
  - शोधकरताओं का सुझाव है कि पूर्ण कार्य मांग को पूरा करने के लिये इसका बजट कम से कम 4 गुना (अरथात् सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.2% से 1.5%) अधिक होना चाहिये।
- जाति-आधारति मजदूरी भुगतान और असमानताएँ:** वर्ष 2021 में शुरू किये गए जाति-आधारति मजदूरी पृथक्करण (जिसके तहत भुगतान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिएवं 'अन्य' शरणियों में वर्गीकृत किया गया) के बाद यह देखा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिके श्रमकों की तुलना में 'अन्य' जाति के श्रमकों के लिये भुगतान में देरी हुई।
  - 'अन्य' जाति के केवल 33% भुगतान 7 दिनों के अंदर संसाधित किये गए, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिये यह आँकड़ा 42% तथा अनुसूचित जातियों के लिये 47% था।

### मनरेगा अधनियम क्या है?

- परिचय:**
  - यह सामाजिक सुरक्षा के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण रोज़गार की गारंटी प्रदान करना है।
  - इसे वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत अधनियमित किया गया था।

- उद्देश्य: अकुशल शारीरिक कार्रवा करने के इच्छुक पंजीकृत वयस्क ग्रामीण परवारों को कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना।
- कवरेज: यह योजना 100% शहरी आबादी वाले ज़िलों को छोड़कर पूरे देश में लागू है।
- मांग-आधारित ढाँचा: मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है; यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होते हैं, जो पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम पारशिरमिक का एक-चौथाई और उसके बाद न्यूनतम पारशिरमिक का आधा होता है।
- वर्किंगरीकृत योजना: इस योजना में आधारिक स्तर पर नियोजन कथि जाने पर ज़ोर दिया जाता है, जिसमें कम से कम 50% कार्रवा ग्रामसभा की सफिराई के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा निषिपादति कथि जाता है।
- निधि साझाकरण: केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का 100% और सामग्री लागत का 75% वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें सामग्री लागत का 25% योगदान देती हैं, जिससे कार्रवा नवयन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है।
- पारशिरमिक भुगतान तंत्र: योजना के अंतर्गत पारशिरमिक, राज्य-विशिष्ट न्यूनतम पारशिरमिक दरों पर आधारित होती है और पारदर्शिता के लिये प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के बैंक या आधार-लकिड खातों में इसका भुगतान कथि जाता है।
  - वलिंबित भुगतान के लिये प्रतिवर्ष अवैतनिक पारशिरमिक की 0.05% प्रतिपूर्तिप्रदान की जाती जाता है, जो उपस्थितिनामावली (Muster Roll) का समापन कथि जाने के 16वें दिन से शुरू होता है।
- दुर्घटना प्रतिप्रति: कार्रवा स्थल पर घायल हुए श्रमिक प्रतिप्रति के पात्र होते हैं तथा मृत्यु अथवा स्थायी दवियांगता की स्थिति में परवारों को अनुग्रह (Ex-Gratia) राशप्रदान की जाती है।
  - MGNREGA लाभार्थियों में एक तहिई महलियों का होना आवश्यक है, जिससे पारशिरमिक और कार्रवा के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

## Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)



## MGNREGA पर प्रमुख नवीनतम आँकड़े

- बजट 2024-25:**
  - मनरेगा आवंटन: मनरेगा बजट वित्त वर्ष 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए था जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए हो गया है।
  - पारशिरमिक दर में वृद्धि: वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूनतम औसत पारशिरमिक दर में 7% की वृद्धि हुई।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24:**
  - महलि भागीदारी: मनरेगा में महलियों की भागीदारी वित्त वर्ष 2019-20 में 54.8% थी जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 58.9% हो गई।
  - जयिटैगणि और पारदर्शिता: मनरेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से परसिंप्ततयों की जयिटैगणि के साथ 99.9% भुगतान सटीकता सुनिश्चित करता है।

## मनरेगा योजना को प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहये?

- प्रयाप्त बजट आवंटन: सरकार को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, ग्रामीण रोज़गार की बढ़ती मांग को पूरा करने और श्रमकों की गरमि और आजीवकिए की रक्षा करने के लिये मनरेगा के बजट आवंटन में वृद्धिकरनी चाहये।
- डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार: सरकार को ABPS जैसी डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार करना चाहये, तकनीकी बाधाओं को दूर करना चाहये, बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना चाहये और वशिष्ठ रूप से ग्रामीण श्रमकों के लिये पहुँच और उपयोगकर्ता-मतिरता सुनिश्चित करनी चाहये।
- जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना: सरकार को देरी के लिये जमिमेदारी लेनी चाहये, मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा सुनिश्चित करना चाहये, और समय पर मजदूरी संवितरण सुनिश्चित करने के लिये रपोर्टिंग, निगरानी और शक्तियां नविरण प्रणालियों में सुधार करना चाहये।
- भावी सुधार: भावी सुधारों में कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहये, जाति-आधारित असमानताओं से बचना चाहये और सभी श्रमकों के लिये उचित व्यवहार सुनिश्चित करना चाहये।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम (MGNREGA) के उद्देश्यों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसकी चुनौतियों का समाधान करने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

### प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखित में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परवारों के वयस्क सदस्य।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परवारों के वयस्क सदस्य।
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परवारों के वयस्क सदस्य।
- (D) कसी भी घर के वयस्क सदस्य।

उत्तर: (D)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/delays-in-mgnrega-wages>